



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102024-258238  
CG-DL-E-25102024-258238

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 25, 2024/कार्तिक 3, 1946

No. 302]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 25, 2024/KARTIKA 3, 1946

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2024

फा. सं. 11/04/2020-समर्थ.— वस्त्र मंत्रालय, समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना) नाम से एक प्रमुख योजना चला रहा है, जिसका उद्देश्य वस्त्र और संबंधित क्षेत्र में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों में सहायता करने के लिए मांग आधारित रोजगार उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है। इसमें संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और वीविंग को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला और हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट, रेशम आदि जैसे विकेन्द्रीकृत पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें प्रवेश स्तर का कौशल और अप-स्किलिंग/री-स्किलिंग प्रशिक्षण, दोनों शामिल हैं।

2. यह योजना, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अपनाई गई समग्र कौशल नीतिगत ढांचे और कौशल कार्यक्रम के संदर्भ में कार्यान्वित की जाती है, जिसे मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

i. राज्य सरकार की एजेंसियाँ

ii. वस्त्र मंत्रालय के संस्थान/संगठन

iii. वस्त्र उद्योग/उद्योग संघ

3. पिछली स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने 390 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 3.40 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3 वर्षों यानी 31.03.2024 तक के लिए योजना को मंजूरी दी थी। अब, स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की सिफारिशों के आधार

पर सक्षम प्राधिकारी ने 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ समर्थ के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को और दो वर्षों की अवधि अर्थात् 2024-25 और 2025-26 (31.03.2026 तक) के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है।

अजय गुप्ता, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

### RESOLUTION

New Delhi, the 23rd October, 2024

**F. No. 11/04/2020-Samarth.**— Ministry of Textiles is implementing a flagship Scheme Samarth (Scheme for Capacity Building in Textiles Sector) with the objective to provide demand driven placement oriented skilling programme to supplement the efforts of the industry in creating employment in textile and related sector, covering the entire value chain of textiles, excluding Spinning & Weaving in organized sector and decentralized traditional sectors such as handloom, handicraft, jute, silk etc. comprising of both entry level skilling and up-skilling/re-skilling training

2. The scheme is implemented in terms of the overall skilling policy framework adopted by M/o Skill Development & Entrepreneurship and the Skilling programme under which is majorly implemented through the following Implementing Partners:

- i. State Government Agencies
- ii. Institutions/ Organizations of the Ministry of Textiles
- iii. Textile Industry/ Industry Associations

3. Previous SFC approved the scheme for 3 years i.e. upto 31.03.2024 with financial outlay of Rs.390 cr. and to train 3.40 lakhs persons. Now, the Competent Authority, based on the recommendations of Standing Finance Committee (SFC) has approved further extension of timeline for implementation of Samarth for a period of two years i.e 2024-25 and 2025-26 (up to 31.03.2026) with financial outlay of Rs. 495 Cr. to train 3 lakh persons.

AJAY GUPTA, Jt. Secy.